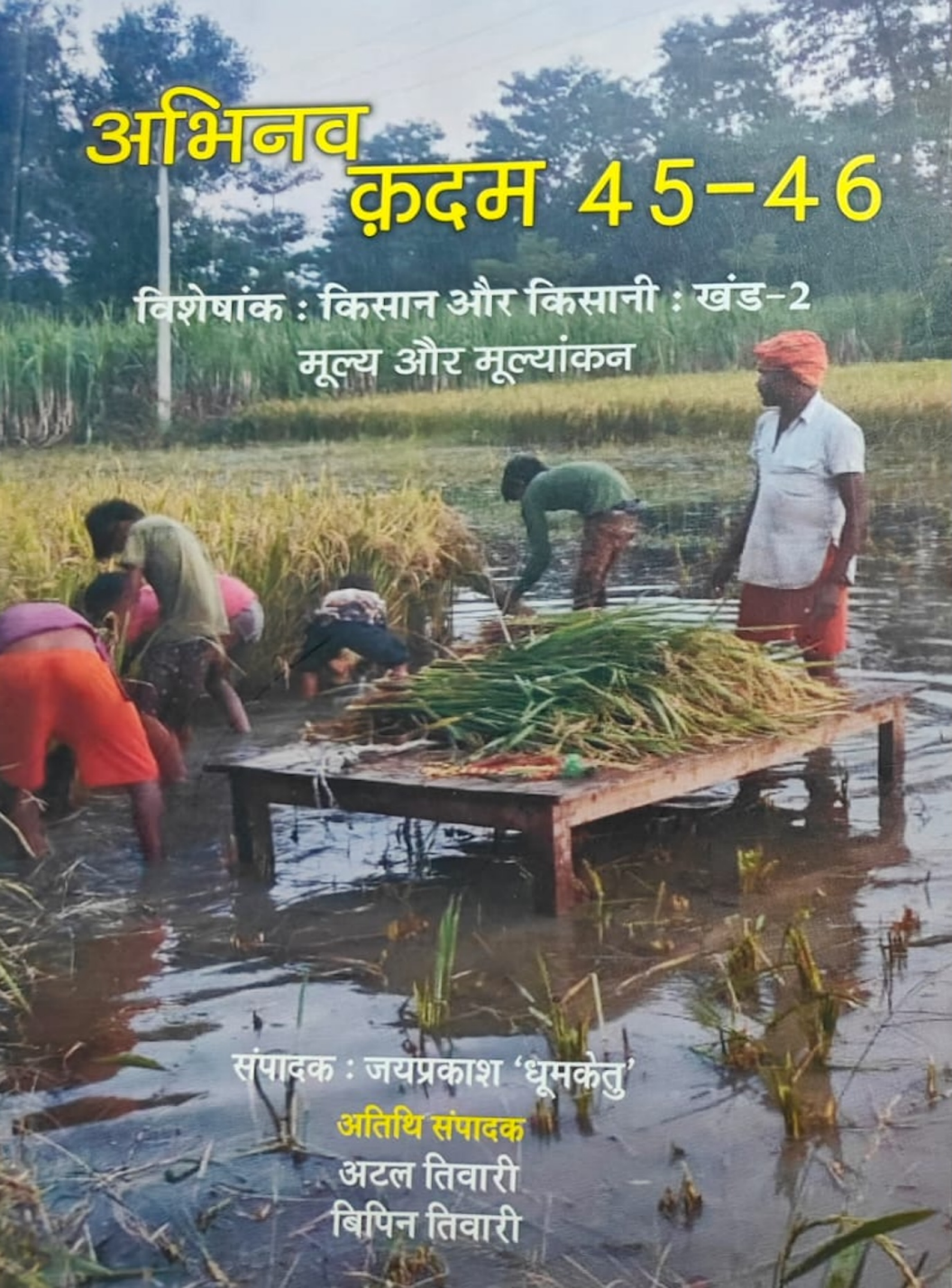

अभिनव क़दम 45-46

विशेषांक : किसान और किसानी : खंड-2
मूल्य और मूल्यांकन

संपादक : जयप्रकाश 'धूमकेतु'

अतिथि संपादक

अटल तिवारी

बिपिन तिवारी

ISSN 2229-4767 RNI No. 72297|99

अभिनव क़दम -45-46

(संयुक्तांक)

किसान विशेषांक :

मूल्य और मूल्यांकन–खण्ड 2

सम्पादक : जयप्रकाश 'धूमकेतु'
अतिथि सम्पादक : अटल तिवारी, बिपिन तिवारी

अभिनव क़दम -45-46 *(संयुक्तांक)*

संपादक

जयप्रकाश 'धूमकेतु'

patrika.abhinavkadam@gmail.com

dhoomketu223@gmail.com

अतिथि संपादक

अटल तिवारी

ataltewari.bjmc@rla.du.ac.in

बिपिन तिवारी

bipintiwari85@gmail.com

उप संपादक

अमरेन्द्र कुमार शर्मा

amrendrakumarsharma@gmail.com

फार्म :: 4

प्रेस तथा पुस्तक पंजीयन अधिनियम के अन्तर्गत 'अभिनव कदम' नामक पत्रिका से संबंधित स्वामित्व और अन्य बातों का विवरण–

1. प्रकाशन	:	223, प्रकाश निकुंज, पावर हाउस रोड, निज़ामुद्दीनपुरा, मऊ (उ.प्र.)
2. प्रकाशन की आवर्तिता	:	अर्द्धवार्षिक
3. मुद्रक का नाम	:	जयप्रकाश धूमकेतु
क्या भारतीय हैं?	:	हाँ
पता	:	223, प्रकाश निकुंज, पावर हाउस रोड, निज़ामुद्दीनपुरा, मऊ (उ.प्र.)
4. प्रकाशक का नाम	:	जयप्रकाश धूमकेतु
क्या भारतीय हैं?	:	हाँ
पता	:	223, प्रकाश निकुंज, पावर हाउस रोड, निज़ामुद्दीनपुरा, मऊ (उ.प्र.)
5. संपादक का नाम	:	जयप्रकाश धूमकेतु
क्या भारतीय हैं?	:	हाँ
पता	:	223, प्रकाश निकुंज, पावर हाउस रोड, निज़ामुद्दीनपुरा, मऊ (उ.प्र.)
6. उन व्यक्तियों के नाम व पते जो पत्रिका के मालिक और कुल पूंजी के एक-एक प्रतिशत से अधिक के हिस्सेदार या भागीदार हैं	:	**राहुल सांस्कृत्यायन सृजन पीठ** साहित्यिक-सांस्कृतिक संस्था, 'मंथन' 223, प्रकाश निकुंज, पावर हाउस रोड, निज़ामुद्दीनपुरा, मऊ (उ.प्र.), पिन-275101

मैं जयप्रकाश धूमकेतु एतद् द्वारा घोषणा करता हूँ कि मेरी जानकारी और विश्वास के अनुसार उपरोक्त विवरण सही है। ***–जय प्रकाश धूमकेतु***

संस्थापक–संरक्षक : अब्दुल बिस्मिल्लाह, जन संस्कृति के पक्ष में जर्नल

वर्ष : 26 अंक : (45-46) (संयुक्तांक) जून 2021 - मई 2022

अभिनव क़दम (45-46) *(संयुक्तांक)*

संपादक : **जयप्रकाश धूमकेतु**
उप-संपादक : अमरेन्द्र कुमार शर्मा
अतिथि संपादक : अटल तिवारी (दिल्ली)
विपिन तिवारी (गोवा)
संपादक मण्डल : डॉ. अवधेश प्रधान
डॉ. गोपाल प्रधान, मनोज सिंह
डॉ. अमित राय, शिवकुमार पराग
प्रसार व्यवस्था : **श्रीमती राजेश्वरी**

संपर्क :

'प्रकाश निकुंज'
223, पावर हाउस रोड, निजामुद्दीनपुरा
मऊनाथ भंजन, मऊ (उ.प्र.)–275101
मोबाइल : 09415246755, 08429366755
ई-मेल : (i) patrika.abhinavkadam@gmail.com
(ii) dhoomketu223@gmail.com
(iii) amrendrakumarsharma@gmail.com
वेबसाइट : www.abhinavkadam.com, www.rahulsankrityan.com

सहयोग राशि

यह अंक	**200.00**
संस्थाओं के लिए	**300.00**
विदेश में	**$ 25**
आजीवन सदस्यता	**5000.00**

प्रकाशक : **राहुल सांकृत्यायन सृजन पीठ**, मऊनाथ भंजन, मऊ (उ.प्र.)
शब्द संयोजन : श्वेताजाब्स, 68 बहादुरगंज, इलाहाबाद E-mail : vs430186@gmail.com
मुद्रण : प्रोग्रेसिव प्रिंटर्स, ए-21, झिलमिल एंड, इंडस्ट्रीयल एरिया, शाहदरा, दिल्ली-95
e-mail: pd.press@gmail.com

संपादन/संचालन/अवैतनिक, अव्यवसायिक। अभिनव कदम से सम्बन्धित सभी विवाद मऊ न्यायालय के अधीन होंगे। अभिनव कदम में प्रकाशित रचनाओं की रीति-नीति या विचारों से संपादक की सहमति अनिवार्य नहीं है।

अनुक्रम

अपनी बात

'दाम सब गोदाम में तुम्हारे'/जयप्रकाश 'धूमकेतु' 1

संपादकीय

कृषि क्षेत्र की बदहाली की वजह क्या?/अटल तिवारी बिपिन तिवारी 6

परम्परा

1. भारत का किसान और राजनीति/सोमपाल शास्त्री 15
2. नवउदारवाद का आक्रामक मॉडल बनाम जन आंदोलन का अनूठा प्रयोग/ अनिल चौधरी 39
3. भारतीय किसानों की नियति और राजनीति/प्रेमकुमार मणि 59

चिन्हाकन

4. सबसे बड़े क्षेत्र में सबसे बड़ा संकट/अशोक धवले 64
5. विकास के नाम पर भू-अधिग्रहणः अनुभव, परिदृश्य और सबक/ अभिषेक श्रीवास्तव 71
6. खेती का संकट और महिलाओं की हस्तक्षेपकारी भूमिका/ जया मेहता और विनीत तिवारी 92
7. सिर्फ खेती से परिवार नहीं चलता, इसलिए नौजवान चुन रहे विकल्प/मनदीप पुनिया और अमित ओहलान 114
8. देशी और जीन परिवर्तित बीज/अरविंद कुमार सिंह 120
9. रासायनिक खाद और कीटनाशकों का प्रयोग/सुभाष चन्द्र कुशवाहा 134
10. रासायनिक खेती के जोखिम बनाम जैविक के संकट/पंकज मिश्र 142
11. उत्तर प्रदेश के गन्ना उत्पादक किसानों की व्यथा/मुशर्रफ अली 146
12. फल-सब्जी की खेती और किसान की मुसीबतें/अरविंद शुक्ला 158
13. बटाईदारों के साथ हो रही खेतों की 'मौत'/योगेश नारायण दीक्षित 162
14. ठेका खेती के लाभ-हानि/प्रीति सिन्हा 168
15. प्राकृतिक और 'सरकार जनित आपदाओं' के बोझ तले किसान/दीप सिंह 173
16. पर्यावरण विनाश और जलवायु परिवर्तन से चौतरफा संकट/हृदयेश जोशी 181
17. तालाबों से सिंचाई के जरिए बच सकती है खेती/पंकज चतुर्वेदी 184
18. पराली के नाम पर किसान को बना दिया खलनायक/डॉ. अनिल चौधरी 188
19. राजनीति के अखाड़े में गो-धन, मुसीबत में किसान/अटल तिवारी 194

मूल्यांकन

20. भारत का कृषि संकटः भूमण्डलीकरण और नई आर्थिक नीति/राजेश मल्ल 216
21. मंडीः अलग-अलग समस्याएं तो समाधान भी अलग-अलग होंगे/अनुराग द्वारी 223
22. प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना में लूट/अर्जुन प्रसाद सिंह 230

23. किसानों का ये कैसा सम्मान?/दया शंकर राय 236
24. बजट, कृषि व किसान/मुकेश असीम 243

साक्षात्कार

25. कृषि संकट अब इंसानियत का संकट बन गया/(पत्रकार पी साईनाथ से अटल तिवारी की बातचीत) 255
26. सोची-समझी रणनीति के तहत 269
27. कृषि को तबाह किया गया (कृषि अर्थशास्त्री और खाद्य विशेषज्ञ देविन्दर शर्मा से अटल तिवारी की बातचीत) 269
28. किसान आंदोलन ने उम्मीद 296
29. जगाने का काम किया (किसान नेता डॉ. सुनीलम से बिपिन तिवारी की बातचीत) 296
30. सरकारें, किसान नहीं कम्पनियों के हित में फैसले लेती हैं (किसान नेता विजय जावंधिया से बिपिन तिवारी की बातचीत) 313
31. किसान संगठनों को राजनीति से दूर रहना चाहिए (क्रान्तिकारी किसान यूनियन के अध्यक्ष डॉ. दर्शनपाल सिंह से अटल तिवारी की बातचीत) 335
32. जिस दिन किसान हड़ताल पर चला जाएगा, दिमाग ठीक हो जाएगा (भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय प्रवक्ता राकेश टिकैत से अटल तिवारी की बातचीत) 353

साहित्य

33. वैश्वीकरणोत्तर हिंदी कविता में किसान जीवन/डॉ. अमरेन्द्र नाथ त्रिपाठी 372
34. किसान जीवन का यथार्थ और हिंदी कहानी का समकाल/अभिषेक गुप्ता 386
35. हिंदी उपन्यास के हतभागे किसान/तरसेम गुजराल 416
36. रंगमंच में किसान और किसानी/राजेश कुमार 445
37. हिंदी फिल्मों में किसान/अजय कुमार 455
38. कृषि क्षेत्र और किसानों का दोहन करने वाला कारोबारी मीडिया/अनिल चमड़िया 464
39. ऑल्टरनेटिव मीडिया से उम्मीद/दिवाकर 475
40. हिंदी लघु पत्रिकाओं में कहां हैं खेती-किसानी के सवाल?/जाहिद खान 482

आन्दोलन

41. किसान आन्दोलन 2021 का हासिल/कमल नयन काबरा 490
42. अहिंसक राजनीति और किसान आंदोलन/अरुण कुमार त्रिपाठी 510
43. वर्तमान दौर में किसान आंदोलन तथा संसद की भूमिका/सुनीत चोपड़ा 520
44. अधूरी जीत की विशेषता और चुनौतियां/बादल सरोज 525
45. महिला किसानों ने आंदोलन को पितृसत्ता के शिकंजे से मुक्त किया/भाषा सिंह 531
46. खेती के संकट की मूल वजहों को समाप्त करने का संकल्प याद रखना होगा/विनीत तिवारी 536
47. सवालों और संकटों से घिरा किसान आंदोलन?/रामशरण जोशी 546

लेखकों के संपर्क सूत्र ***556***

अपनी बात

'दाम सब गोदाम में तुम्हारे'

''सरसों के फूल सब हमारे
दाम सब गोदाम में तुम्हारे''

खेती और किसानी पर अभिनव क़दम के विशेषांक का दूसरा खण्ड मूल्य और मूल्यांकन-खण्ड के रूप में पाठकों के बीच जा रहा है। वस्तुतः इस अंक में विगत वर्षों में मोदी सरकार द्वारा लाए गए तीनों कृषि कानूनों के विरुद्ध किसान आंदोलन का उभार देश भर के 400 से अधिक छोटे-बड़े किसान संगठनों के संयुक्त किसान मोर्चा का दिल्ली की परिधि पर सिंधू बार्डर, टिकरी बार्डर, गाजीपुर बार्डर पर महापड़ाव और शान्तिपूर्ण ढंग से लगभग तेरह महीनों तक चले आन्दोलन में 732 किसानों की शहादत और सरकार द्वारा जन विरोधी-किसान विरोधी तीनों कृषि कानूनों को वापस लिया जाना किसानों के संघर्ष की उपलब्धि रही। परन्तु खतरा अभी टला नहीं है। ऐसे समय में बनारस के मेरे करीबी मित्र जयप्रकाश बागी जो अब इस दुनिया में नहीं हैं. का एक गीत याद आता है, जो आज के दौर में सटीक बैठता है—**''सरसों के फूल सब हमारे, दाम सब गोदाम में तुम्हारे''**। दरअसल कृषि हमारे देश का ऐसा उद्योग है जिस पर सबसे अधिक आबादी निर्भर है। इसीलिए आजादी के बाद से ही सरकार की चिंता का प्रमुख विमर्श भी कृषि क्षेत्र रहा है।

प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने देश में सामूहिक और सहकारी खेती का प्रस्ताव रखा था जिसे स्वीकार नहीं किया गया।

1986 में राजीव गांधी के वित्त मंत्री वी.पी. सिंह द्वारा 22 कृषि उत्पादों का न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) तय किया गया।

1990 में प्रधानमंत्री वी पी सिंह के कार्यकाल में तीन समितियां गठित की गई—

1. भानुप्रताप सिंह की अध्यक्षता में—केन्द्र सरकार की कृषि नीतियों की विशद समीक्षा एवं उनमें सुधार।
2. शरद जोशी की अध्यक्षता में कृषि मूल्य नीति।
3. हनुमन्त राव की अध्यक्षता में—भूमिहीन किसान-मजदूरों की समस्या।

भानुप्रताप सिंह कमेटी की रिपोर्ट को कृषि एवं ग्रामीण विकास के समग्र समाधान की बाइबिल कहा गया।

अंग्रेजी सरकार 1907 के कृषि कानूनों को आंदोलन के दबाव में वापस लेने को बाध्य हुई थी, लेकिन उद्योगों को कच्चे माल की आपूर्ति के लिए उन्होंने नील की खेती के लिए किसानों को बाध्य किया। यह अंग्रेजी सरकार द्वारा कॉरपोरेट फार्मिंग का ही एक तरह का प्रयास था जिसके विरुद्ध लोकप्रिय किसान आंदोलन चला।

1991 से लागू की गई नवउदारवादी आर्थिक नीतियों की निरंतरता आज तक कायम है। 2014 के बाद तो इन साम्राज्यपरस्त नीतियों की रफ्तार में बेतहाशा वृद्धि हुई।

नवउदारवादी नीतियों के आने और साम्राज्यवादी अमेरिका के दबाव में देश की कृषि नीतियों में हुए बदलावों ने भारतीय जनमानस खासकर किसान समुदाय के समक्ष गहरा संकट पैदा कर दिया। किसान एक तरफ कर्ज के जाल में फंसते गए और दूसरी ओर कृषि लागत मंहगी होने, कृषि उत्पादों की समुचित मूल्य पर खरीद न हो पाने की स्थिति ने संकट को और भी गहरा कर दिया। किसानों के अंदर खदबदाते गुस्से का पहला बड़ा विस्फोट मध्य प्रदेश के मंदसौर में हुआ, जहां उपरोक्त प्रश्नों पर आंदोलन कर रहे किसानों पर गोलियां चलाई गई और कई किसान शहीद हुए। मंदसौर काण्ड के बाद पूरे देश में किसान आंदोलन फैलने लगा। लगभग ढाई सौ से अधिक किसान संगठन एक साथ आए और अखिल भारतीय किसान संघर्ष समन्वय समिति (एआईकेएससीसी) का गठन हुआ। देश भर में किसान यात्राएं निकाली गई जिसका समापन जंतर-मंतर पर तीन दिवसीय किसान महापड़ाव के रूप में हुआ। जनद्रोही तीन कृषि कानूनों के अस्तित्व में आने से पूर्व ही कॉरपोरेट घरानों द्वारा कृषि उत्पादों के भण्डारण के लिए अति आधुनिक सुविधाओं और तकनीक से सुसज्जित भण्डारण गृहों (साइलों) का निर्माण कराया जाने लगा। अडानी के भण्डारण गृहों का निर्माण पंजाब, हरियाणा समेत देश के कई प्रांतों में किया गया। सरकार द्वारा भूमि परिवहन की सभी वांछित सुविधाएं कॉरपोरेट घरानों को उपलब्ध करा दी गईं। भण्डारण की निर्धारित सीमाएं हटा दी गईं। जितना चाहो भण्डारण करो और जब चाहो बाजार को मुट्ठी में कर लो। अर्थात् खाद्यान्न-सब्जी-फलों का पूरा बाजार कुछ मुट्ठी भर कॉरपोरेट घरानों के नियंत्रण में। इन तैयारियों से लगता है कि इन जनद्रोही-किसान विरोधी कृषि कानूनों का ड्राफ्ट कॉरपोरेट घरानों ने तैयार कर व्यवस्था के मुखिया को थमा दिया हो। 2020 में किसान विरोधी तीन अध्यादेश आने के बाद पंजाब में किसान सड़कों पर उतर पड़े। आपदा में अवसर के अपने क्रूर सिद्धांत पर चलते हुए मोदी सरकार ने जब इन अध्यादेशों को कोविड महामारी के कारण लागू सख्त लॉकडाउन के समय में कानून में बदला तो देशभर के किसान आंदोलित हो उठे। एआईकेएससीसी और पंजाब के किसानों ने संयुक्त रूप से दिल्ली मार्च का ऐलान किया। मार्च को रोकने की कोशिश

में सरकार ने किसानों के साथ क्रूर एवं बर्बर व्यवहार किया। अंततः दिल्ली की बाहरी सीमाओं पर किसान महापड़ाव की शुरुआत हुई और संयुक्त किसान मोर्चा की नींव पड़ी।

'एक दिन पलट जायेगी किसानों-मजदूरों की दमनकारी दुनिया। हमें पूरा विश्वास है—हम होंगे कामयाब एक दिन'। यथार्थ की जमीन खदबदा रही है। अस्मिताओं की हिफाजत के लिए उठने लगी हैं आवाजें। जल-जंगल-जमीन की अनुगूंज सुनाई पड़ने लगी है (मोर्चे पर विदा गीत-विहाग वैभव, कविता संग्रह)।

हर खेतों की मेड़ें-किसान-मजदूरों के मंगलसूत्र हैं, घर-घरनी और आंगन में ठुमकते बेटे-बेटियों का भविष्य। फसलों का घरों में आना ही रखता है मंगलसूत्र की बुनियाद। जिस बुनियाद को हड़प लेना चाहती है व्यवस्था की खूंखार आंखें।

''एक भूख सदियों से पीछा करती है एक आदिम कराह सीने पर सारंगी की तरह बजती रहती है तुम ध्यान से देखोगे तो तुम्हें मेरी पीठ पर कोड़ों के हजार निशान मिलेंगे मां कहती है जन्मजात हैं निशान'। (हासिए की तीव्र संवेदना)

बहुत मामूली सी चीजें चाही थी उन्होंने—विहाग वैभव

'वे हमारे सभ्य होने के इंतजार में हैं हम उनके मनुष्य होने के' (कवियत्री जसिन्ता केरकेट्टा—ईश्वर और बाजार-तीसरा संग्रह)

'सरयू नदिया कहर घाघरा **अगम बहे दरियाव,** रे भाई अगम बहे दरियाव!! शिवमूर्ति का चर्चित उपन्यास गाँव और किसान की जिन्दगी का आना है, गोदान और मेला आंचल की तरह।

लूट और फूट के मुकम्मल इंतजाम की बदौलत व्यवस्था कॉरपोरेट फार्मिंग की दिशा में निरंतर आगे बढ़ रही है। धर्म और जाति की वर्णवादी विभाजनकारी शक्तियां वैशाखी का काम कर रही है।

जमींदारी प्रथा की समाप्ति के बाद भी किसानों के जीवन में कोई बदलाव नहीं आया, भले ही हल बैल की जगह ट्रैक्टर, थ्रेसर आ गए—''देसवा होई गवा सुखारी हम भिखारी रह गए''। उद्योगपतियों-पूंजीपतियों के उत्पादों के लिए अधिकतम खुदरा मूल्य (एमआरपी) की व्यवस्था है और किसानों की उपज के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) की गारंटी भी नहीं। श्रम की लूट का मुकम्मल इंतजाम व्यवस्था की नियति है।

सरकार पूंजीपतियों के हजारों-हजार करोड के कर्ज माफ कर रही है, उन्हें पुनः कर्ज दे रही है और किसान महाजनों, बैंकों और सरकारी कर्जा के बोझ तले कराह रहे हैं एवं आत्महत्या कर रहे हैं। सरकार की सह पर कई पूंजीपति हजारों करोड़ बैंकों से लेकर विदेश भाग गए हैं। किसानों की तबाहकारी कर्जों से मुक्ति दिलाने की वजाय